खबर संक्षेप

मतदाताओं से प्राप्त गणना पत्रक का करें शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशनः कलेक्टर

शहडोल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. केदार सिंह ने अनुविभगीय राजस्व कार्यालय जैतपुर के सभागार में जैतपुर अनुविभाग के अंतर्गत विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान 2026 के तहत किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बीएलओ, बीएलओ सुपरवाईजर एवं एसआईआर कार्य में संलग्न कर्मचारियो को निर्देश दिए कि मतदाताओ से प्राप्त गणना पत्रक के डाटा को बीएलओ ऐप में शत-प्रतिशत फीडिंग करते हुए डिजिटाइजेषन करें। उन्होंने कहा कि एसआईआर के कार्यों को प्राथमिकता एवं गंभीरता के साथ करे जिससे किसी भी प्रकार की गडबड़ी न हो यह सुनिष्चित करें। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतपुर दीपक मंडावी सहित बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहें।

छात्रावासों एवं नगरीय निकायो में की गई अलाव की व्यवस्था

शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह निर्देशानुसार ठंड के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए जिले के विभिन्न छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों के लिए अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसी प्रकार नगरीय निकाय धनपुरी के विभिन्न चौराहो एवं प्रमुख स्थानो पर ठंड से बचने हेतु लोगो के लिए अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अलाव की व्यवस्था आने जाने वाले वाहन चालको व नागरिकों को ठंड से बचने में काफी मददगार साबित होती है। शहरी क्षेत्र के निराश्रित लोगो को नगरपालिका टीमो द्वारा सर्वे कर रैन बसेरा एवं सुरक्षित स्थानो में ठहरने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है।

आज रोजगार मेला

शहडोल। प्राचार्य संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण श्री एसके वर्मा ने जानकारी दी है कि एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन 20 नवम्बर 2025 को शासकीय संभागीय आईटीआई परिसर में किया जाएगा। रोजगार मेला में व्हील्स इंडिया लिमिटेड रंजन गांव पूणे, एसआईएस सिक्योरिटी, ग्रोफास्ट एग्रीटेक प्रायवेट लिमिटेड जबलपुर सहित अन्य कम्पनिया शामिल होगी। रोजगार मेले में सहभागिता की अभिस्वीकृति दिवाकर सिंह जिला रोजगार कार्यालय को मोबाइल नम्बर 9407813779 एवं ई मेल पर अनिवार्य रूप से प्रदाय करें।

बबुआ का संरक्षण, राजस्व-रजिस्ट्री तंत्र की सहभागिता जिला प्रशासन बना मूकदर्शक

बरूका में धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग!

> भू-माफिया अवैध प्लाटिंग का खेल खुलेआम खेल रहे हैं। किसानों की जमीन को पहले औने-पौने दामों में खरीद लेते हैं। फिर नियम विरुद्ध बिना नक्शा व आवासीय प्लाट दर्ज कराए प्रति प्लाट लाखों रुपये में बेचते हैं। इस प्लाटिंग के खेल में रजिस्ट्री कार्यालय के अधिकारी भी शामिल हैं, लेकिन आगे इसका खामियाजा भू-खंड खरीदने वाले लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, यह तय है।
> शहडोल।

संभागीय मुख्यालय से लगे बरूका क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग का खेल इन दिनों अपने चरम पर है। स्थानीय ग्रामीणों, शिकायतकर्ताओं और क्षेत्रीय सामाजिक संगठनों का आरोप है कि यह पूरा अवैध कारोबार खुले संरक्षण में फल-फूल रहा है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि बरूका में चल रहे इस प्लाटिंग महोत्सव के पीछे कथित रूप से बबुआ का मजबूत संरक्षण है, जिसके चलते जिला प्रशासन से लेकर तहसील, रजिस्ट्री कार्यालय और पटवारी तक का अमला लगभग निर्बल और मौन दिखाई दे रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि बरूका, छतवई, पोंगरी और आस-पास के इलाक़ों में कृषि भूमि को टुकड़ों में बेचने का धंधा वर्षों से चल रहा था, लेकिन अब यह कारोबार इतने खुले तरीके से सामने आने लगा है कि राजस्व अमले की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

कृषि भूमि बेचने का धंधा

बरूका में एक ही खसरा नंबर की कृषि भूमि को कई भागों में बांटकर रजिस्ट्री की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सब कुछ बिना मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता। रजिस्टार कार्यालय में बैठे जिम्मेदार अधिकारी दस्तावेज़ों पर मुहर लगा रहे हैं, जबकि नियम साफ तौर पर कृषि भूमि को 'कॉलोनी के रूप में' बेचने की अनुमति नहीं देते। सूत्रों का कहना है कि फाइलें सीधे कलेक्टर कार्यालय तक पहुंची हैं, कई शिकायतें सोशल मीडिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी दर्ज कराई गईं, परंतु कार्रवाई का न होना प्रशासन की नीयत पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

अवैध प्लाटिंग का नया मॉडल

वैध कॉलोनाइज़ जहां सडक़, पानी, बिजली और पार्क जैसी सुविधाएँ देने के लिए 50 प्रतिशत भूमि विकास कार्यों में लगाते हैं, वहीं बरूका सहित अन्य क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग करने वालों ने सिर्फ मुरूम डालकर दो कच्ची सडक़ें बना दीं और बाकी 80 प्रतिशत जमीन प्लॉट के रूप में बेचने की तैयारी कर ली है, यह पूरा खेल केवल भू-माफिया का फायदा बढ़ाने के लिए किया जाता है, जबकि खरीदारों को न बिजली मिलती है, न पानी और न ही ड्रेनेज व्यवस्था, कई खरीदारों ने बताया कि प्लाट खरीदने के बाद उन्हें पता चला कि यह पूरी जमीन कृषि श्रेणी में दर्ज है।

बबुआ का संरक्षण?

बरूका क्षेत्र के ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अवैध प्लाटिंग का यह पूरा नेटवर्क एक खास व्यक्ति जिसे इलाके में बबुआ के नाम से जाना जाता है, उसके संरक्षण में चलता है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना उसके निर्देश के न प्लाट कटता है, न रजिस्ट्री होती है और न ही राजस्व अमले के अधिकारी क्षेत्र में कदम रखते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन की चुप्पी से साफ है कि ऊपर तक सबकुछ सेट है। नहीं तो इतनी बड़ी प्लाटिंग कोई कैसे कर लेता?

राजस्व तंत्र की भूमिका संदिग्ध

बरूका सहित कई गांवों में राजस्व विभाग के कर्मचारी और पटवारी इस खेल में शामिल है, ग्रामीणों का कहना है कि उनकी मौजूदगी में अवैध प्लाटिंग होना ही अपने-आप में बड़ा सवाल है। शिकायतें लगातार की गईं, परंतु तहसील स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तत्कालीन कलेक्टर ने पूर्व में ऐसे कई मामलों में दंडात्मक कार्रवाई का इरादा जताया था, लेकिन वह मामले भी समय के साथ ठंडे बस्ते में डाल दिए गए।

रजिस्ट्री कार्यालय 'सुविधा केंद्र'

अवैध प्लाटिंग में सबसे बड़ी भूमिका रजिस्टार कार्यालय की मानी जा रही है, जहां एक ही खसरा नंबर से दस-दस टुकड़ों में रजिस्ट्री करने में बिना किसी रोक-टोक के दस्तावेजों को स्वीकार किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि फिट का खेल वर्षों से चल रहा है और अवैध प्लाटिंग की हर रजिस्ट्री में उस फिट का हिस्सा तय रहता है।

भू-स्वामियों पर लगेगी रासुका!

राज्य सरकार की तैयारी है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने के बजाय अवैध प्लाटिंग करने वाले भू-स्वामियों पर रासुका जैसे कड़े प्रावधान लागू किए जाएं। साथ ही जिस क्षेत्र में अवैध कॉलोनी पाई जाएगी, वहां के राजस्व अधिकारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी को भी सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस संभावित कानून की जानकारी सामने आने के बाद भी बरूका में अवैध प्लाटिंग का सिलसिला जारी है, जिससे साफ है कि अवैध कारोबार करने वालों को प्रशासनिक कार्रवाई का कोई भय नहीं है।

धूल खा रहे दर्जनों प्रकरण

बरूका और आस-पास की अवैध प्लाटिंग के कई मामले वर्षों से कलेक्टर कार्यालय में लंबित हैं, लेकिन वास्तविक कार्रवाई आज तक नहीं हो सकी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मामले जानबूझकर दबाए जाते हैं, ताकि प्लाटिंग का धंधा बिना रुकावट चलता रहे। बरूका में अवैध प्लाटिंग का यह पूरा खेल केवल कानून के उल्लंघन का मामला नहीं, बल्कि जिला प्रशासन, रजिस्टार कार्यालय और राजस्व अमले की निष्क्रियता या फिर कथित मिलीभगत का एक बड़ा उदाहरण बन चुका है।

इनका कहना है...

मुझे इस क्षेत्र में आये हुए लगभग एक से डेढ़ माह हुए हैं, वर्तमान में एसआईआर का कार्य चल रहा है, मेरे कार्यकाल के दौरान एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई है, अगर अवैध प्लाटिंग हो रही है तो, इसकी जानकारी नहीं है।

विनय तिवारी
पटवारी, हल्का बरूका

अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के तहत आयोजित किया गया प्रशिक्षण

शहडोल।

केंद्रीय सहकारी बैंक मर्यादित सभागार में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत 72 वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम में इफको उप क्षेत्र प्रबंधक इफको शहडोल राजेश कुमार मौर्य ने कृषि, किसान और सहकारिता के विकास के योगदान में इफको द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा की। उन्होंने कृषक द्वारा वर्तमान समय में उर्वरक के बढ़ते असंतुलित उपयोग को कम कर जैव उर्वरक, नैनो उर्वरक, नैनो डीएपी और सागरिका के बारे में बताया। कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रभारी वैज्ञानिक मृगेंद्र सिंह ने फसलों में उपयोग होने वाले पोषक तत्वों के कार्य और संतुलित उर्वरक उपयोग, जैविक खेती तथा नैनो उर्वरकों के प्रयोग और लाभ के बारे में बताया और कृषकों को इसके सही उपयोग के लिए जागरूक करने हेतु कृषक गोष्ठी के लिए कहा। सहायक संचालक कृषि कल्याण श्री कैलाश मगर ने प्रधानमंत्री धन धान्य योजना अंतर्गत कृषि और किसान के हित में योजनाओं और सहकारिता के योगदान सहित अन्य विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग शहडोल श्रीमती सुरेखा आनंद अहिरवार, सहायक आयुक्त सहकारिता अभय सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस.के.यादव सहित जिला सहकारी बैंक शहडोल के सभी शाखा प्रबंधक और समिति प्रबंधक उपस्थित रहे।

23 नवंबर को प्रदेश प्रभारी के आगमन को लेकर बैठक सम्पन्न

इंदिरा गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि

शहडोल।

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय अवस्थी की अध्यक्षता में कांग्रेस भवन में सोमवार को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। साथ ही 23 नवंबर को मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी हरीश चौधरी के शहडोल आगमन की तैयारियों को अंतिम रूप देने हेतु बैठक आयोजित की गई।

कार्यक्रम की शुरुआत इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके उपरांत उपस्थित नेताओं ने उनके देशहित में किए गए निर्णयों, संघर्षों और उनके बलिदान को याद किया। जिलाध्यक्ष अजय अवस्थी ने कहा कि इंदिरा गांधी केवल एक राजनेता नहीं थीं, बल्कि भारत की राजनीतिक दृढ़ता, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की सशक्त प्रतीक थीं। उन्होंने कहा कि आर्थिक अस्थिरता और चुनौतियों के दौर में इंदिरा गांधी ने जिस मजबूत इच्छाशक्ति के साथ देश का नेतृत्व किया, वह आज भी प्रेरणा देता है।

श्री अवस्थी ने उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि 1966 में पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने निर्णायक फैसले लिए। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय और बांग्लादेश के गठन ने उन्हें विश्व पटल पर 'आयरन लेडी' की पहचान दिलाई। 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण ने देश को परमाणु संपन्न राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा किया। हरित क्रांति को आगे बढ़ाकर उन्होंने कृषि क्षेत्र को नई दिशा दी और खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाई। बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे कदमों ने गरीब तबके को आर्थिक मजबूती प्रदान की। बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के आगामी दौरे को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष ने बताया कि चौधरी 23 नवंबर को सुबह 11 बजे जिला समन्वय समिति की बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे वे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित समीक्षा बैठक लेंगे और दोपहर 3 बजे से कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं आमजन से इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराने की अपील की।

इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल, पूर्व उपाध्यक्ष कुलदीप निगम, वरिष्ठ कांग्रेस नेता महमूद अहमद, मुबारक मास्टर, जनपद अध्यक्ष उमा धुर्वे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नरेन्द्र मरावी, पूर्व पार्षद प्रभात पाण्डेय, जिला मुख्य प्रवक्ता पीयूष शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष अनुज मिश्रा, बुढ़ार ब्लॉक अध्यक्ष राजीव शर्मा, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनुपम गौतम, उपाध्यक्ष आशीष तिवारी, सोशल मीडिया जिलाध्यक्ष प्रीतेश द्विवेदी, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सौरभ तिवारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

छात्रों को दिया गया डिजिटल सुरक्षा का प्रशिक्षण

शहडोल।

जिले में बढ़ते साइबर अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी के खतरे को देखते हुए शहडोल पुलिस ने जिलेभर में **व्यापक साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर छात्रों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के उपाय और साइबर अपराधों से बचाव के तरीकों से अवगत कराना है।

इस पहल का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक रामजी श्रीवास्तव कर रहे हैं। अभियान के तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम, संवाद सत्र और सार्वजनिक जानकारी प्रसार गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों में छात्रों, शिक्षक और आम नागरिक शामिल होकर अपने डिजिटल व्यवहार को सुरक्षित बनाने के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

अभियान की मुख्य गतिविधियों के तहत 18 नवम्बर 2025 को सायबर सेल टीम ने सेंट ज्यूड्स हाईयर सेकेंडरी स्कूल, सिंहपुर रोड, शहडोल में छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में छात्रों को इंटरनेट उपयोग के दौरान सुरक्षित रहने की आवश्यक सावधानियों और साइबर अपराधों के नवीनतम तरीकों के बारे में जागरूक किया गया।

छात्रों को डिजिटल सुरक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया गया और उन्हें निम्नलिखित शपथ लेने के लिए प्रेरित किया गया। किसी भी संदिग्ध लिंक, ईमेल या संदेश पर क्लिक नहीं करना। अज्ञात स्त्रोतों से मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड नहीं करना। बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी किसी के साथ साझा न करना। किसी भी साइबर अपराध या ऑनलाइन धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करना। साइबर अपराध रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों को राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और नजदीकी थाना या साइबर सेल से संपर्क करने के निर्देश दिए गए। शहडोल पुलिस का यह अभियान छात्रों में डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और साइबर अपराधों से बचाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। पुलिस का उद्देश्य है कि छात्र और आम नागरिक साइबर दुनिया में सतर्क और सुरक्षित बने रहें और किसी भी ऑनलाइन धोखाधड़ी का सामना न करें। इस प्रकार शहडोल पुलिस ने डिजिटल सुरक्षा को लेकर सख्त और सतर्कता भरा संदेश सभी नागरिकों तक पहुँचाया।

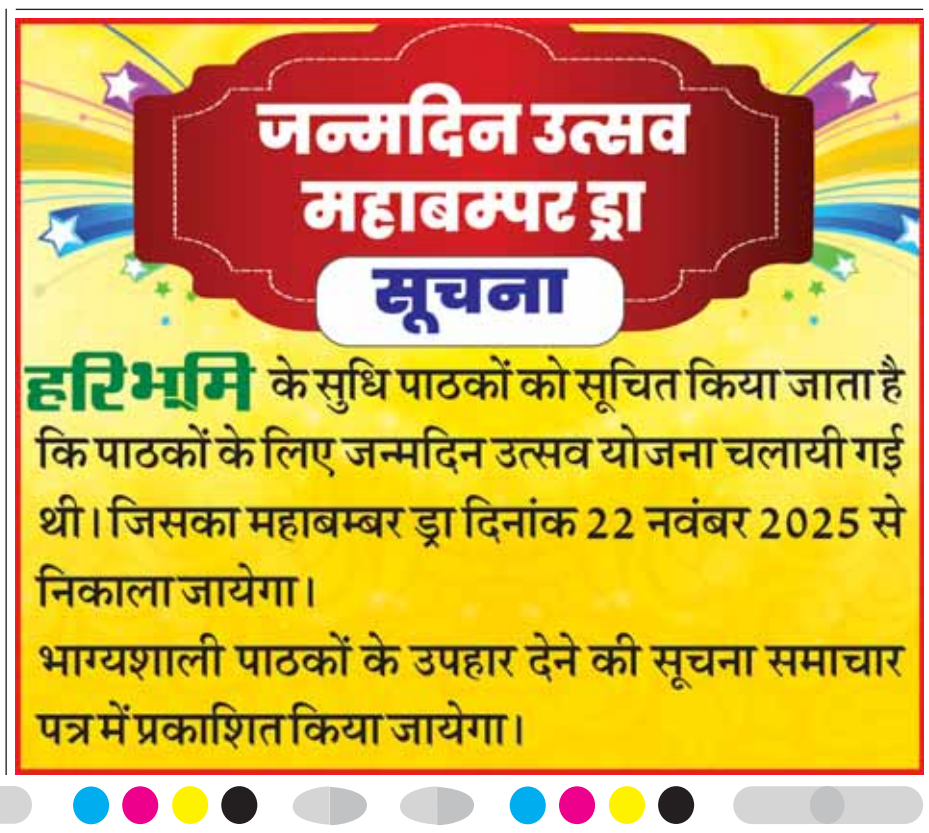

खबर संक्षेप

अनूपपुर इकाई का चुनाव संपन्न

हरिभूमि न्यूज कोतमा। 16 नवम्बर को मध्यप्रदेश बैंक मित्र संगठन की अनूपपुर इकाई का चुनाव संपन्न कराया गया जहां समरेंद्र चंद्र दास को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चयनित किया गया तथा कृष्ण कुमार शर्मा को सचिव बनाया गया और कोषाध्यक्ष ओपी और मीडिया प्रभारी राकेश साहू और राकेश अनूपपुर जिले की कार्यकारणी का गठन व संगठन बनाया गया जिसमें बैंक मित्र और बैंक सखी द्वारा चुनाव को संपन्न किया गया। यह आयोजन एक निजी भवन में संपन्न हुआ जिसमें सभी लोग उपस्थित थे।

सहा. शिक्षक व प्रभारी प्रधानाध्यापक इन्द्रपाल दहायत निलंबित

उमरिया। निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण निर्वाचन कार्य में लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की खुलेआम अवहेलना करने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने इन्द्रपाल दहायत सहायक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक, शासकीय हाई स्कूल असोढ (विकासखंड मानपुर) को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय उमरिया निर्धारित किया गया है तथा वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर पूरे प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रत्येक बीएलओ प्रतिदिन कम-से-कम 10 प्रतिशत गणना-पत्रक डिजिटाइजेशन का कार्य अनिवार्य रूप से पूरा करे तथा बीएलओ सुपरवाइजर इस कार्य की सतत निगरानी करें। इन्द्रपाल दहायत को विधानसभा क्षेत्र 90-मानपुर के मतदान केंद्र क्रमांक 21 से 30 तक के लिए बीएलओ सुपरवाइजर नियुक्त किया गया था। लेकिन प्रशासनिक समीक्षा में पाया गया कि उनके पर्यवेक्षण में आने वाले मतदान केंद्रों में गणना-पत्रक डिजिटाइजेशन का कार्य महज 6 प्रतिशत से भी कम किया गया, जो पूर्णतः असत्य एवं भ्रामक आंकड़ा साबित हुआ।

दो शिक्षकों पर वेतन वृद्धि रोकने की सजा

बीएलओ की लापरवाही पर कलेक्टर की कठोर कार्रवाई

तीन बीएलओ एवं एक सचिव को कारण बताओ नोटिस

उमरिया। निर्वाचन कार्य जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ के विरुद्ध जिला प्रशासन अब सख्त रुख अपनाता दिख रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दो बीएलओ को एक-एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की दंडात्मक कार्रवाई की गई है, जबकि तीन बीएलओ एवं एक सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

प्रा. शिक्षक पर अनुशासनात्मक कार्रवाई

प्राथमिक शिक्षक, शा.मा.शाला बिछिया, विकासखंड करकेली एवं मतदान केन्द्र क्रमांक 284-बिछिया (विधानसभा क्षेत्र 89-बांधवगढ़) के बीएलओ मान सिंह उइके पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-10 के तहत आगामी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की सजा अधिरोपित की गई है। निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की कार्रवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिदिन न्यूनतम 10त्न गणना-पत्रक डिजिटाइजेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके विपरीत मान सिंह उइके द्वारा 697 मतदाताओं में से मात्र 9 (1.29त्न) मतदाताओं का ही डिजिटाइजेशन किया गया, जो प्रशासनिक जाँच में असत्य पाया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि बीएलओ ने न तो क्षेत्र में भ्रमण किया और न ही मतदाताओं से संपर्क साधा। शाम की गूगल मीट समीक्षा बैठक में उपस्थिति के बावजूद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यह स्थिति उनके निर्वाचन कार्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना को दर्शाती है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

मा. शिक्षक पर वेतनवृद्धि रोकने की सजा

माध्यमिक शिक्षक शासकीय उमावि भरेवा, विकासखण्ड मानपुर एवं मतदान केन्द्र क्रमांक 19-बसेहा (विधानसभा क्षेत्र 90-मानपुर) के बीएलओ बृजेश कुमार मिश्रा के विरुद्ध भी समान प्रकृति की अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। कुल 688 मतदाताओं में से उन्होंने मात्र 4 (0.58 प्रतिशत) मतदाताओं का ही डिजिटाइजेशन किया। यह आंकड़ा भी गलत पाया गया। बीएलओ द्वारा क्षेत्र में सतत भ्रमण न करने और मतदाताओं से संपर्क नहीं करने की पुष्टि हुई। समीक्षा के दौरान उन्हें गूगल मीट में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन उन्होंने आदेश की अवहेलना करते हुए बैठक में शामिल होने की भी जहमत नहीं उठाई। यह कृत्य भी उनकी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर उदासीनता और आयोग के निर्देशों की अवमानना को दर्शाता है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कलेक्टर द्वारा उनकी एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाने का आदेश जारी किया गया है।

तीन बीएलओ, एक सचिव को नोटिस

निर्वाचन कार्य की धीमी प्रगति और आदेशों की अनुपालना न करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने तीन बीएलओ और एक सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जवाब संतोषजनक न होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। नोटिस प्राप्त करने वाले अधिकारी-कर्मचारी अशोक कुमार परस्ते, माध्यमिक शिक्षक, उमावि शाला कुमारमंगलम नौरोजाबाद एवं बीएलओ, मतदान केंद्र 240 खोदरवगवां (89-बांधवगढ़), नारायण सिंह उइके, माध्यमिक शिक्षक, शा. उमावि लोढा एवं बीएलओ, मतदान केंद्र 25 लोढा (89-बांधवगढ़), मुक्तिप्रभा तिर्की, प्राथमिक शिक्षक, प्रा. शाला वार्ड 3 सुभाषगंज उमरिया एवं बीएलओ, मतदान केंद्र 142 बांधवगढ़, शिखा गुप्ता, सचिव, ग्राम पंचायत धनवाही, जनपद पंचायत करकेली, जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अस्वीकार्य है। निर्वाचन कार्य अत्यंत संवेदनशील एवं प्राथमिकता वाला दायित्व है, जिसमें अपेक्षित प्रगति न होने पर कठोर कदम उठाए जाते रहेंगे। इस सख्त कार्रवाई के बाद अन्य बीएलओ और जिम्मेदार अधिकारियों को भी स्पष्ट संदेश दिया गया है कि समयसीमा, लक्ष्य एवं आयोग के निर्देशों का पूर्ण पालन अनिवार्य है।

नायब तहसीलदार मानपुर को कारण बताओ नोटिस

जिला प्रशासन ने दिखाई कठोरता उमरिया। जिले में निर्वाचन कार्य की सुस्ती और अधिकारियों की उदासीनता पर जिला प्रशासन ने अब सख्त तेवर अपना लिए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार, मानपुर सनत कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि वे निर्धारित समय-सीमा में लिखित जवाब समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाएगा।

निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. के निर्देशानुसार बीएलओ द्वारा गणना पत्रक का वितरण, वापसी एवं डिजिटाइजेशन का कार्य प्रतिदिन निर्धारित प्रगति के अनुसार पूरा कराने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय नोडल अधिकारियों पर सौंपी गई है। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र 90-मानपुर के मतदान केन्द्र क्रमांक 151 से 225 तक की मॉनिटरिंग का दायित्व नायब तहसीलदार सनत कुमार को सौंपा गया था। उन्हें प्रतिदिन फील्ड में जाकर बीएलओ एवं सुपरवाइजरों से संपर्क करने और समय-सीमा में कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन जिला प्रशासन की जांच में पाया गया कि आवंटित मतदान केंद्रों पर गणना पत्रक डिजिटाइजेशन अत्यंत कम रहा। जबकि आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में स्पष्ट किया था कि डिजिटाइजेशन कम-से-कम 20 प्रतिशत प्रतिदिन किया जाए। निर्धारित लक्ष्य से बेहद निम्न प्रगति पर जब दूरभाष के माध्यम से नायब तहसीलदार से जानकारी चाही गई तो न केवल वे संतोषजनक जवाब देने में विफल रहे, बल्कि उन्होंने फील्ड में न जाने को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वाहन उपलब्ध न होने की बात कहकर स्वयं को तहसील कार्यालय में उपस्थित बताया। एक ओर आयोग निर्वाचन सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने हेतु गहन पुनरीक्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान मानकर निर्देश दे रहा है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी का ऐसा रवैया गंभीर चिंता का विषय बन गया है। प्रशासन का कहना है कि नायब तहसीलदार का यह कृत्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जरा भी रुचि नहीं ली, न ही अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा दिखाई। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की यह खुली अवहेलना स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में आती है। कलेक्टर द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि अधिकारी का व्यवहार म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है और इसे कदाचार माना जाएगा। बताया गया है कि निर्वाचन जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में इस प्रकार की लापरवाही को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन की इस कठोर कार्रवाई को पूरे जिले के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि निर्वाचन कार्य में शिथिलता, लापरवाही या वरिष्ठ अधिकारियों की अवहेलना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगले चरण में क्या दंडात्मक कार्रवाई होती है, यह नायब तहसीलदार के जवाब पर निर्भर करेगा, लेकिन प्रशासन का रुख साफ है, जिम्मेदारी निभानी ही होगी, अन्यथा कार्रवाई तय है।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में प्रशासन सख्त

मानपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण

उमरिया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को पूरी गंभीरता के साथ संचालित किया जा रहा है। मतदाता सूची को अद्यतन, त्रुटिरहित और वास्तविक स्थिति के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं, गणना पत्रकों की दो प्रतियाँ वितरित कर रहे हैं तथा मोबाइल एप पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से मतदाता विवरण को अपडेट कर रहे हैं।

इसी कड़ी में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मानपुर हरनीत कौर कलसी ने मतदान केंद्र क्रमांक 185 बरतराई, 188 कोडार एवं 155 बिजौरी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीएलओ के कार्य की प्रगति की समीक्षा की तथा स्पष्ट निर्देश दिए कि एसआईआर कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए बीएलओ निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य प्राप्त करें और घर-घर सत्यापन की कार्रवाई को प्राथमिकता से पूर्ण करें। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदाताओं से बातचीत भी की और उन्हें प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया कि बीएलओ के पास मतदाता सूची 2025 के विवरण के आधार पर पूर्व-भरा (प्री-प्रिंटेड) एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध है। मतदाताओं को इसमें

दर्ज नाम, पता और इपिक नंबर सहित सभी सूचनाओं को ध्यानपूर्वक जांचना चाहिए और किसी भी त्रुटि या परिवर्तन की जानकारी तत्क्षण बीएलओ को देनी चाहिए।उन्होंने कहा कि जिन परिवारों में कोई नया सदस्य 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उन्हें फॉर्म-6 भरकर नाम जोडऩा अनिवार्य है। वहीं यदि परिवार का कोई सदस्य निधन हो गया है या किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो गया है, तो उसकी सूचना भी तुरंत दी जाए ताकि मतदाता सूची से उसका नाम विलोपित किया जा सके। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बीएलओ को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि एसआईआर कार्य आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और निर्देशों की अवहेलना मिलने पर कठोर कार्रवाई से किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। घर-घर सत्यापन पूर्ण होने के पश्चात 9 दिसंबर 2025 को प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक नागरिक अपने नाम से संबंधित दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची का यह पुनरीक्षण लोकतंत्र की आधारशिला है और इसकी शुद्धता के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। बीएलओ को इस महत्वपूर्ण कार्य को लेकर पूरी जवाबदेही एवं तत्परता प्रदर्शित करनी होगी।

नगर परिषद बनगवां में बनकर तैयार हुआ सामुदायिक शौचालय

हरिभूमि न्यूज़ राजनगर। नगर परिषद बनगवां (राजनगर) में 19 नवंबर को न्यू राजनगर में थाना रामनगर के ठीक सामने निर्मित सामुदायिक शौचालय का भव्य उद्घाटन किया गया। नगर परिषद बनगवां (राजनगर) के वरिष्ठ नागरिक विनोद तिवारी के हाथों फीता काटकर सार्वजनिक शौचालय का लोकार्पण किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष यशवंत सिंह एवं उपाध्यक्ष धनंजय सिंह सहित कार्यक्रम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी राम मिलन तिवारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलेश चतुर्वेदी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सुरेश गौतम, वरिष्ठ नागरिक विनोद तिवारी, सामाजिक कार्यकर्ता सचिन द्विवेदी, नारायण साहू, अनुराग तिवारी, अरविंद वर्मा,हरीलाल साकेत, पत्रकार साथी मुनेंद्र यादव, मनीष सिंह, मनुमणि तिवारी, विशेष रूप से उपस्थित रहे।

क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी सुविधा

कार्यक्रम में थाना रामनगर के थाना प्रभारी सुमित कौशिक की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। वार्ड क्रमांक 6 की पार्षद सबिता बृजेश कुशवाहा, वार्ड क्रमांक 9 के पार्षद मनोज चंदेल, तथा वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद समय पटेल ने कहा कि सामुदायिक शौचालय का निर्माण क्षेत्र की वर्षों पुरानी आवश्यकता थी। जिससे स्थानीय नागरिकों को अब साफ-सुथरी और सुरक्षित सुविधा उपलब्ध होगी। उद्घाटन समारोह में नगर बनगवां (राजनगर) परिषद के लेखापाल राजेश मिश्रा, बृजेश कुशवाहा, अनिल सिंह, अनुराग तिवारी सहित नगर परिषद के कई कर्मचारी और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। अध्यक्ष यशवंत सिंह ने बताया, कि नगर परिषद का उद्देश्य क्षेत्र में स्वच्छता व नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ मजबूत करना है। आने वाले समय में भी जनहित की और परियोजनाएँ शुरू की जाएँगी। नई सुविधा के शुरू होने से क्षेत्रवासियों को स्वच्छता अभियान का सीधा लाभ मिलेगा और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो सकेगी।

गुमशुदा कटौतियों के निराकरण हेतु शिविर प्रारंभ

उमरिया। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने बताया कि गुमशुदा कटौतियों एवं अप्रविष्ट मदों के निराकरण के लिए जिला कोषालय जबलपुर में जीपीएफ समाधान शिविर प्रारंभ कर दिया गया है, जो 21 नवंबर तक आयोजित रहेगा। शिविर का उद्देश्य लंबे समय से लंबित जीपीएफ संबंधित त्रुटियों और कटौती विसंगतियों का त्वरित निपटान करना है। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि जिन कर्मचारी-अधिकारियों की जीपीएफ गुमशुदा कटौतियों से संबंधित शिकायतें लंबित हैं, वे अनिवार्य रूप से शिविर में उपस्थित होकर अपना प्रकरण समाधान हेतु प्रस्तुत करें।

मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर रेलवे स्टेशन

शौचालय, पेयजल सहित बैठने की उचित व्यवस्था तक नही यात्री सुविधाओं पर रेलवे का उदासीन रवैया

हरिभूमि न्यूज कोतमा। कोतमा रेलवे स्टेशन मे अव्यवस्थाओ का अंबर लगा हुआ है यहां पर आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। देखने को तो जगह जगह शौचालय बना हुआ है पर उसमें ताला लटका रहता है और लोगो को शुद्ध पेयजल तो छोड़ो समुचित पानी ही नहीं मिल पा रहा है। रेलवे स्टेशन परिसर में गंदगी का अंबार लगा रहता है। कोतमा रेलवे स्टेशन जहां मूलभूत सुविधाओं के नाम पर सिर्फ दिखावा बचा है यात्रियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है और न ही पीने के लिए शुद्ध पेय जल की व्यवस्था है और सुलभ शौचालय सिर्फ दिखावे के लिए बना हुआ है क्योंकि यहां सिर्फ ताला लगा ही देखने को मिलता है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दिनभर आना जाना लगा रहता है। परंतु आने जाने वाले यात्रियों को सुलभ शौचालय की सुविधा नही मिलती न ही पीने के लिए पर्याप्त पानी साथ ही गंदगी का अंबार लगा रहता है। रेलवे प्रबंधन इस पर अपना ध्यान आकर्षित करना उचित नही समझती है। जिसका जीता जगता उद्धरण सामने देखने को मिल रहा है। आखिर रेलवे प्रबंधन क्यो नही सुविधा मुहैया करा रहा है आखिर किसकी लापरवाही की वजह से यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जबकि यह क्षेत्र कोयलांचल क्षेत्र होने के साथ ही कोतमा नगर आर्थिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथ ही एक दर्जन से अधिक सवारी गाड़ियों का आना-जाना हैऔर प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्रियों का आवागमन रेलवे स्टेशन पर बना रहता है। सबसे ज्यादा पीने के पानी की परेशानी गरीब तपके के लोगों को होती है। बड़े लोग तो पैंक बोतल पानी लेकर पी लेते हैं। स्टेशन परिसर मे जो नल की टोपियां लगी है उनमें से एक या दो टोटी से पानी निकलता है बाकी बंद पड़े हैं।

गंदगी की भरमार तो प्रसाधन मे गंदगी

वर्तमान में रेलवे स्टेशन के अंदर नालियां गंदगी से भरी पड़ी हुई है जगह-जगह गंदगी देखने को मिल रही है। जबकि रेलवे प्रबंधन के द्वारा रेलवे स्टेशन की साफ सफाई के लिए ठेकेदार के माध्यम से साफ सफाई की व्यवस्था सौपी गई है लेकिन स्टेशन परिसर का भ्रमण करने पर साफ सफाई की पोल खुलती नजर आ रही है। नाली गंदगी से पटी है जिसके कारण दुर्गंध से यात्री परेशान रहते हैं। स्टेशन परिसर में पेशाब करने के लिए प्रशाधन बनवाया गया है लेकिन वह पूरी तरह से गंदगी से भरी पड़ी हुई है जिसके कारण यात्रियों को रेलवे स्टेशन के बाहर प्रशाधन करने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। गंदगी के कारण प्रशाधन से बदबू आ रही है।

महिलाओं को होती है परेशानी

ग्रामीण क्षेत्र से यात्रा करने रेलवे स्टेशन आई महिला ने बताया कि हम काम से हर दूसरे तीसरे दिन कोतमा रेलवे स्टेशन में यात्रा करने आते हैं लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी हम लोगों को पेशाब जाने के लिए होती है स्टेशन में बने शौचालय में हमेशा ताला लटकता रहता है। जिसके कारण हम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। रेलवे स्टेशन में पीने के लिए पानी की भी पर्याप्त सुविधा नहीं है एक या दो टोटी से पानी निकलता है बाकी शोपीस बन गये हैं जिसके लिए हमें स्टेशन के बाहर बाजार में जाकर

पानी खरीद कर पीना पड़ता है। हम लोगों के साथ छोटे-छोटे बच्चे भी रहते हैं जिन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि रेल प्रबंधन को कोयलांचल क्षेत्र होने के कारण जमकर राजस्व का लाभ होता है उसके बाद भी कोतमा रेलवे स्टेशन के साथ रेल प्रबंधन का सौतेला व्यवहार समझ से परे है। नागरिकों ने रेल प्रबंधन से रेलवे स्टेशन में शौचालय की सुविधा एवं पीने की पानी की सुविधा प्रदान करने की मांग की है।

खुली नालियों से खतरा

रेलवे प्रबंधन द्वारा रेलवे स्टेशन एवं परिसर में बनाए गए नालियों में चेंबर नहीं लगाए गए हैं जिसके कारण नालियों में गंदगी भरी पड़ी हुई है बारिश का पानी जब नाली में भर जाता है तो वह रेलवे स्टेशन के अंदर तक आ जाता है। नालियों में गंदगी भरी पड़ी होने के कारण मच्छर भी पनपते हैं जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक ओर पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत रेलवे स्टेशन परिसर में यदि कोई व्यक्ति खड़ा होकर पेशाब कर रहा है तो उस पर रेलवे प्रबंधन के द्वारा जुर्माना लगाया जाता है और वहीं दूसरी ओर यह देखने को मिल रहा है कि रेलवे स्टेशन में स्वच्छता के नाम पर दिखावा किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश करने के साथ ही पाइप लगाई गई थी जिसके कारण जानवर स्टेशन परिसर में प्रवेश नही कर पाते थे लेकिन रेलवे प्रबंधन के द्वारा उस पाइप को भी निकाल लिया गया है जिसके कारण मूक पशु प्लेटफार्म के अंदर तक पहुंच जाते हैं जिसके कारण कई मूक पशुओं की सवारी गाड़ियों के नीचे आने से मौत भी हो चुकी है। लेकिन रेलवे प्रबंधन व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्लेटफार्म के अंदर हर समय आवारा कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है इनको प्लेटफार्म के अंदर आराम फरमाते हर समय देखा जा सकता है। आवारा कुत्तों के प्लेटफार्म के अंदर विचरण करने के कारण यात्रियों को भय बना रहता है। रेल प्रबंधन खुले आम सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहा है।

खबर संक्षेप

पुलिस की जनसुनवाई में 33 आवेदकों ने बताई समस्याएं

कटनी। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन में मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनके निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित निराकरण को सुनिश्चित करना है। आयोजित जनसुनवाई में कुल 33 आवेदकों ने विभिन्न प्रकरणों से जुड़ी शिकायतें और आवेदन प्रस्तुत किए। एसपी विश्वकर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया सहित अन्य राजपत्रित अधिकारियों ने उपस्थित होकर प्रत्येक आवेदक की समस्या को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। अधिकारियों ने संबंधित थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए कि सभी प्राप्त आवेदनों पर तत्काल और प्रभावी कार्यवाही की जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके तथा पुलिस-जन विश्वास और अधिक मजबूत हो।

देवरी मंगेला हार में नरवाई में लगाई आग

उमरियापान। प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में नरवाई जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देवरी मंगेला हार में मुख्य सड़क के किनारे किसानों ने खेतों में आग लगाकर नरवाई जलाई। आग खेतों में बढ़ती गई। धान की कटाई के बाद कई किसान अगली फसल की तैयारी के लिए खेतों में बचे अवशेष को आग के हवाले कर रहे हैं। जिससे पर्यावरण के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी तेजी से प्रभावित हो रही है। नरवाई जलने से मिट्टी में मौजूद कार्बन, जैविक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता घटती है और फसल उत्पादन पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। धुएं के कारण ग्रामीण इलाकों में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे बुजुर्गों और बच्चों में सांस संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। किसानों का कहना है कि मजदूरों की कमी, मशीनों की अनुपलब्धता और समय की बचत के उद्देश्य से किसान नरवाई जलाते हैं।

जानकारी संकलित करने कर्मचारियों की लगी ड्यूटी

कटनी। आगामी 13 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु विभिन्न खंडपीठों से जानकारी संकलित करने के लिए कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 17 में लगाई गई है। जारी आदेश के अनुसार जानकारी संकलन कार्य के लिये विवेक मुले, अधीक्षक, भू-अभिलेख को प्रभारी बनाया गया है। जबकि राजस्व निरीक्षक बृज बिहारी दुबे को समस्त खंडपीठों से जानकारी प्राप्त करने का दायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार सहायक ग्रेड-तीन ओमप्रकाश तिवारी, शैलेन्द्र देशमुख, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, भृत्य गणेशन पिल्ले और संतोष धुर्वे को कार्यालयीन कार्यवाही का दायित्व सौंपा गया है।

द्वारका-सोमनाथ यात्रा के लिए आवेदन आमंत्रित

कटनी। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत द्वारका-सोमनाथ यात्रा के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह यात्रा 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। कटनी जिले के लिए इस यात्रा में कुल 250 बर्थ आवंटित किए गए हैं। यात्रा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर तक निर्धारित की गई है। द्वारका-सोमनाथ तीर्थयात्रा के आवेदन पत्र जमा करने एवं संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम आयुक्त और सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट www.dharmasva.mp.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु के पति-पत्नी (महिला को 2 वर्ष की छूट) आवेदन कर सकते हैं। 65 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक अपने साथ एक सहायक ले जा सकते हैं।

नगर पालिका कार्यालय से अटल द्वार तक रोजाना उड़ रही धूल से लोग बेहाल

धनपुरी मॉडल रोड पर धूल का कहर

डामरीकरण की गुणवत्ता पर उठे सवाल

नगर पालिका कार्यालय से अटल द्वार तक निर्मित मॉडल रोड इन दिनों स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। लगभग दो वर्ष पूर्व सीमेंटकृत सड़क के ऊपर डामरीकरण कराया गया था, लेकिन हाल ही में हुई बरसात के बाद सड़क की ऊपरी परत जगह-जगह से उखड़ने लगी है।

धनपुरी।

डामरीकृत सतह के टूटते ही छोटे-छोटे गिट्टियां बाहर निकल आई हैं, जिससे सड़क पर बड़े वाहन गुजरते ही धूल का बवंडर उठने लगता है।रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार में निकलने वाले भारी वाहनों के पीछे धूल का ऐसा फव्वारा उठता है कि दोपहिया और छोटे वाहनों को चलाना मुश्किल हो जाता है। धूल हवा में फैलने से एलर्जी, आंखों में जलन और सांस संबंधी दिक्कतें बढ़ रही हैं।स्थानीय रहवासियों ने बताया कि इसी मार्ग पर छोटे बच्चों का स्कूल भी संचालित होता है। बच्चों के आने-जाने के समय धूल की मात्रा और बढ़ जाती है, जिससे अभिभावक गंभीर रूप से चिंतित हैं। कई बार बच्चे धूल के कारण खांसी और एलर्जी की शिकायत लेकर घर पहुंच रहे हैं।कोयले से भरे भारी वाहनों की निरंतर आवाजाही से समस्या और गंभीर हो गई है। इन वाहनों के गुजरते ही सड़क पर जमा धूल एकदम से हवा में उड़कर पूरे क्षेत्र को ढक लेती है। सुबह-शाम धूल का घना गुबार उठने से दुकानदारों और राहगीरों का जीना मुहाल हो गया है।रहवासियों का कहना है कि सड़क निर्माण के समय गुणवत्ता पर सही ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते महज दो वर्ष में ही रोड टूटने लगी है। लोगों ने नगरपालिका प्रशासन से मांग की है कि सड़क की तत्काल मरम्मत करवाई जाए और धूल से राहत के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराया जाए।"सड़क टूटने से धूल की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। छोटे बच्चों और दोपहिया चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। प्रशासन को स्थिति सुधारने तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।" — स्थानीय नागरिकधनपुरी के लोगों की यह मांग है कि खराब सड़क की मरम्मत के साथ ही भारी वाहनों के संचालन पर भी नियंत्रित रफ्तार और वैकल्पिक मार्ग जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएं, जिससे लगातार उठ रही धूल से राहत मिल सके।

विश्वविद्यालय में पांच दिवसीय मत्स्य जागरूकता कार्यक्रम

शहडोल।

पंडित शंभू नाथ शुक्ला विश्वविद्यालय के मत्स्य विभाग द्वारा विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर के अवसर पर पांच दिवसीय एकीकृत फिशरीज जागरूकता एवं कौशल विकास कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद द्वारा प्रायोजित था, जबकि सह-प्रायोजक के रूप में एलआईसी, पहला अनाया अकैडमी, जन परिषद और जय ऑटोमोबाइल जुड़े। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं आमजन में मत्स्य पालन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और कौशल विकास कर उन्हें उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराना था।कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रोफेसर भरत शरण सिंह, पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय नियामक आयोग मध्य प्रदेश, ने किया। अध्यक्षता प्रोफेसर विनय कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक एवं पूर्व कुलसचिव पंडित यमुना शुक्ल विश्वविद्यालय ने की। कार्यक्रम का आयोजन डॉ. वंदना राम ने सफलतापूर्वक संचालित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मत्स्य विशेषज्ञ और सफल किसान विद्यार्थियों के साथ जुड़े। इनमें से अधिकांश विशेषज्ञ सीधे विद्यार्थियों के साथ अनुभव साझा कर रहे थे। विशेष अतिथि मुकेश रंजन प्रसाद, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम ने विद्यार्थियों को उद्यमिता और आर्थिक प्रबंधन पर मार्गदर्शन दिया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर भरत शरण सिंह ने बताया कि मछली पालन न केवल आधुनिक युग की आवश्यकता है, बल्कि यह प्राचीन काल से चली आ रही विधि है जो आर्थिक एवं शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा, मत्स्य विज्ञान और लोकल कौशल पर आधारित रोजगार सृजन के अवसरों के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में सक्षम रैकवार, आर्नामेंटल फिश फार्मिंग एक्सपर्ट छतरपुर और आदित्य कुमार, बृजेश ठाकुर, पवन कुमार साहू सहित अन्य विशेषज्ञों ने मछली पालन की आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक विधि से प्रजनन और फिश फूड उत्पादन जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया। साथ ही, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने स्टार्टअप एका फ्रेंड का परिचय दिया, जिसमें शिवम भट्ट, कैवल्य प्रजापति और पीयूष मिश्रा शामिल हैं। डॉ. वंदना राम ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को न केवल रोजगार उपलब्ध कराना है, बल्कि समाज में नए रोजगार सृजन के अवसर भी पैदा करना है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. ममता प्रजापति ने किया, जबकि विभागीय स्टाफ और आयोजन समिति के सभी सदस्यों ने इसे सफल बनाने में योगदान दिया। इस पांच दिवसीय कार्यक्रम में राजा मिश्रा, राजपाल पाटले, किरण मिश्रा, अंजलि पटेल, दीपक विश्नोई सहित बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम ने विद्यार्थियों में मत्स्य पालन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें व्यावसायिक दृष्टि से सक्षम बनाने में अहम भूमिका निभाई।

कांग्रेस पार्टी का बीएलए 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

विधानसभा क्षेत्र 87 का जिला कांग्रेस कार्यालय अनूपपुर में प्रशिक्षण शिविर मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक राम अशोक शर्मा पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष सिंगरौली के मुख्य आतिथ्य एवं जिला कांग्रेस कमेटी अनूपपुर के अध्यक्ष गुड्डू चौहान की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अनूपपुर विधानसभा मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रभारी राजीव सिंह ने कार्यक्रम को आवश्यक जानकारी दी, उपस्थित बीएलए 2 को सिलसिलेवार तरीके से गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की बारीकियों से अवगत कराते हुए सभी मतदाताओं को सहयोग प्रदान करने को कहा गया। जिला प्रभारी एस आई आर अनूपपुर जीवेन्द्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रत्येक मतदाताओं को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए कहा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुड्डू चौहान ने सभी बीएलए 2 से कहाँ कि समन्वय स्थापित कर सभी मतदाताओं से संवाद स्थापित करते हुए आने वाली बाधाओं को दूर कर मतदाताओं को सहयोग करें। सिंगरौली जिले से आए राम अशोक शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि सबका दायित्व है कि किसी भी नाम को लेकर मतदाताओं को जागरूक किया जाना आवश्यक है, बीएलओ से समन्वय बनाकर उन्हें पूरा सहयोग प्रदान करें। प्रशिक्षण शिविर को राम खेलावन राठौर पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अनूपपुर, बाबा खान, राकेश गुप्ता, सत्येन्द्र स्वरूप दुबे, पुरुषोत्तम चौधरी, रफ़ी अहमद, आशुतोष सिंह मार्को ने संबोधित करते हुए गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम संबंधित प्रकाश डाला। इस अवसर पर आयरन लेडी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया।

रिहायशी इलाके में भालू की आहट से खौफजदा क्षेत्रवासी

भूखे भालू ने कचरे में ढूंढा खाना

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

जिस तरह इंसानों की पहुंच जंगल तक पहुंच रही है, जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवास सिकुड़ते जा रहे हैं। जिस वजह से आए दिन वन्यजीव जानवर भोजन की तलाश में रिहायशी इलाके का रुख कर रहे हैं। यही कारण है कि मानव और उनके बीच द्वन्द बढ़ता जा रहा है। अनूपपुर से इसी से जुड़ा एक मार्मिक वीडियो सामने आया है, जहां भूख से बेहाल एक भालू रहवासी जगह पहुंच गया और कचरे में खाना ढूंढकर अपनी भूख शांत करता दिखा। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, ताजा मामला नगर परिषद डोला के वार्ड क्रमांक 4 का है, जहां देर रात एक बड़ा भालू रिहायशी इलाके में पहुंच गया। खाने की तलाश में भटकता यह भालू घरों के बाहर पड़े कचरे के ढेर तक आ पहुंचा और पैकेट में रखी खाने की सामग्री को खाता रहा। इस दौरान आसपास के लोग दहशत में घरों के भीतर कैद रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भालू कुछ देर तक मोहल्ले में घूमता रहा और फिर कचरे के ढेर से खाने का सामान चुन-चुनकर खाता रहा। इस दौरान एक युवक ने साहस दिखाते हुए दूर से ही भालू की गतिविधियों का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से जंगली जानवर भोजन की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में लगातार डर का माहौल बना हुआ है। घटना की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है। विभागीय टीम ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और लोगों को रात में बाहर न निकलने और कचरा खुले में न फेंकने की अपील की है। भालू की यह चौंकाने वाली मौजूदगी और उसका वायरल वीडियो अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है।

10 बजे से होगा आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन

शहडोल।

कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने आदेश जारी कर शीतऋतु को दृष्टिगत रखते हुए जिलांतर्गत संचालित आंगनवाडी केन्द्रों के संचालन के समय में आंशिक परिवर्तन करते हुए सुबह 9.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे के स्थान पर आंगनवाडी केन्द्रों का संचालन समय सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक नियत किया है।

सिटीजन चार्टर में चिन्हित सेवाएं समय-सीमा में दी जाएं: कलेक्टर

फोटो क्रमांक-09

शहडोल। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह नें समय-सीमा की बैठक में लोग सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत सिटीजन चार्टर के तहत निर्धारित समय-सीमा में दी जाने वाली चिन्हित सेवाओं के आवेदनों का निराकरण करनें के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही समाधान एक दिवस के तहत प्राप्त आवेदनों का भी निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत दी जाने वाली सेवाओं की विभागवार समीक्षा भी की। आपने यह भी निर्देश दिए कि नवम्बर माह के लिए समाधान ऑनलाईन अंतर्गत जिन विभागों की जिन सेवाओं की समीक्षा की जानी है, उन सेवाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को समय पर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत शिवम प्रजापति, अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रगति वर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती अन्तोनिया एक्का, सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एसडीएम ने विद्यार्थियों को दी एसआईआर की जानकारी

हरिभूमि न्यूज ⏭ कटनी

शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों के सहयोग से स्वीप गतिविधि के अंतर्गत मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करने हेतु एसडीएम प्रमोद चतुर्वेदी के निर्देशन में कार्यशाला का आयोजन हुआ।

कार्यशाला में एसडीएम ने एसआईआर की प्रक्रिया को विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझाते हुये कहा कि इसका मूल मकसद वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट करना है। इसका मुख्य उद्देश्य फर्जी मतदाताओं के नाम हटाना, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम को डिलीट करना और जो छूट गए हैं उनके नाम को जोड़ना शामिल है।

एचपी गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ताओं में नाराजगी

शहडोल।

जिले में एचपी गैस सिलेंडर की गंभीर कमी ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। संभागीय मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों तक गैस गोदामों में सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं की लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन अधिकांश लोग निर्धारित समय पर सिलेंडर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इस बीच, कई जगह सिलेंडर अधिक मूल्य पर बेचे जाने की भी शिकायतें सामने आई हैं। केशवाही क्षेत्र में स्थित एचपी गैस गोदाम में उपभोक्ताओं को तय 880 रुपये के बजाय 900 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति कई दिनों से बनी हुई है, लेकिन संबंधित अधिकारियों की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। उपभोक्ता इस्लाम ने बताया कि मजबूरी में उन्हें अधिक दाम चुकाकर सिलेंडर लेना पड़ा। वहीं, राजेश सिंह ने बताया कि वे एक सप्ताह से सिलेंडर के लिए चक्कर काट रहे थे, अंततः मजबूरी में 900 रुपये देकर ही सिलेंडर मिल पाया।

विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली के बाद से जिले में एचपी गैस की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही, जिससे न केवल आम उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, बल्कि कालाबाजारी और मनमाने दाम वसूलने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। गोदामों में रोज़ाना लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लेकिन कई बार लोग खाली हाथ लौटने को मजबूर हो रहे हैं। स्थानीय निवासी इस स्थिति को गंभीर मानते हुए प्रशासन से शीघ्र सप्लाई को नियमित करने और कालाबाजारी रोकने की मांग कर रहे हैं। वहीं, अधिकारियों की निष्क्रियता से उपभोक्ताओं में गुस्सा और असंतोष बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि यदि जल्द ही गैस की आपूर्ति सही तरीके से नहीं की गई, तो जिले के कई हिस्सों में उपभोक्ताओं की परेशानियां और बढ़ेंगी, और कालाबाजारी के मामलों में वृद्धि होगी।

इनका कहना है...

गैस की शॉर्टेज है, लेकिन इसकी कालाबाजारी से उन्होंने इंकार किया। उनका कहना है कि आपूर्ति पर नजर रखी जा रही है और स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी।

विपिन पटेल
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी
शहडोल

खबर संक्षेप

अभा क्षत्रिय समाज ने आयोजित किया कार्यक्रम

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर। 16 नवम्बर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास में बाल दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज अनूपपुर की सभी बहनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी बहनों ने समय निकालकर अपनी सहभागिता प्रदान कर अनुशासन, पर्यावरण, नशा जैसी बुरी आदतों से दूरी, बाल अपराध, योग, आदि पर विचार व्यक्त किए गये। साथ ही बच्चों को निशुल्क स्नैक्स वा स्टेशनरी वितरण किया। बच्चों के साथ ही छात्रावास के अधीक्षक अनिल कुमार सिंह एवं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ की संरक्षिका, श्रीमती कुमकुम सिंह बघेल, श्रीमती मीना सिंह श्रीमती मनीषा राजपूत श्रीमती बिंदु सिंह, श्रीमती रंजीता तोमर एवं सुश्री मनोरमा सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्षा श्रीमती मीना सिंह ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की सुश्री मनोरमा सिंह ने आभार व्यक्त किया।

सौतेली बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोपी बाप पुलिस गिरफ्त मे

अनूपपुर। पुलिस अधीक्षक मोती-उर-रहमान के निर्देशन मे, अति. पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ मरकाम तथा अनु.अधि. कोतमा (पुलिस) श्रीमती आरती शाक्य के मार्गदर्शन में थाना भालूमाड़ा पुलिस द्वारा अप.क्र. 423/2025 धारा 64(2)(एफ), 64(2)(एम), 351(3) बीएनएस 5(एल), 5(एन), 6 पाक्सो एक्ट के आरोपी विनोद कुमार चौधरी पिता रामनाथ चौधरी उम्र 38 वर्ष निवासी चोंडी पोंडी थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर जो अपने ही सौतेली नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौने कृत्य कर घटना दिनांक से फरार था जिसे थाना प्रभारी भालूमाडा के कुशल नेतृत्व में दो महिने से फरार आरोपी विनोद चौधरी को 19 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया जहाँ से आरोपी को जिला जेल अनूपपुर भेजा गया। आरोपी को पकडने थाना प्रभारी भालूमाडा उप निरी. विपुल शुक्ला, प्रधान आरक्षक कृपाल सिंह, सुखेन्द्र सिंह, आरक्षक अभिषेक राजपूत तथा रविन्द्र मौर्य की भूमिका रही।

जनजातीय भाषा व संस्कृति को समुदाय से जोड़ने में उपयोगी आदि वाणी एप

अनूपपुर। समावेशी जनजातीय सशक्तिकरण और भाषाई संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक पहल के रूप में भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदि वाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित अनुवाद एप और वेब पोर्टल है जो जनजातीय भाषाओ जैसे- भीली, गोडी, संथाली, मुंडारी को हिंदी और अंग्रेजी जैसे मुख्य भाषाओ में अनुवादित करने के लिए है। जिससे जनजातीय संस्कृति और भाषाओं का संरक्षण हो सके शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं तक पहुंच में सुधार हो और डिजिटल सशक्तिकरण हो आदि वाणी एप और वेब पोर्टल जनजातीय समुदायों की लुप्त प्राय भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने और मुख्य धारा से जोड़ता है। आदि वाणी एप और वेब पोर्टल टेक्स्ट, वॉइस और दस्तावेजों का रियल टाइम अनुवाद करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और बड़े भाषा मॉडल (एलएलएम) पर आधारित तकनीक है। आदि वाणी एप जनजातीय भाषाओ और संस्कृति का डिजिटलीकरण और संरक्षण के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन में जनजातीय लोगों की मदद करना व आदि कर्मयोगी पहल के स्वयंसेवकों को सशक्त करना है। भाषा सांस्कृतिक पहचान का आधार है और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसे दृष्टिगत रख भारत सरकार का आदि वाणी एप दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और आदि कर्मयोगी ढांचे के तहत अंतिम छोर तक सेवाओं की आपूर्ति में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

आधी-अधूरी जानकारी व सर्वर की समस्या ने बढ़ाई टेंशन

घर-घर दस्तक देकर गणना पत्रक कर रहे वितरित

एसआईआर मे लापरवाही पर बीएलओ निलंबित

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर/कोतमा।

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुद्धिकरण का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है। बीएलओ घर-घर दस्तक देकर गणना पत्रक वितरित कर रहे हैं और फार्म भरकर वापस जमा कर रहे हैं। जिससे ऑनलाइन डाटा फीड किया जाएगा। यह प्रक्रिया आगामी 4 दिसंबर तक चलेगी। पत्रक भरने में सबसे ज्यादा परेशानी 2003 के विधानसभा निर्वाचन में भाग संख्या तथा क्रम संख्या को लेकर आ रही है। मतदाताओं के पास 22 साल पुरानी जानकारी नहीं है। 2003 की जानकारी उपलब्ध न होने से बीएलओ भी परेशान हो रहे है कारण मतदाता अपना फार्म जमा ही नहीं कर रहे हैं। लोग मतदाता से संबंधित पोर्टल पर जानकारी ढूंढने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। लेकिन वेबसाइट में सर्वर की समस्या लगातार आ रही है। मतदाताओं को स्वयं 2003 के वोटर लिस्ट की जानकारी कियोस्क से लेकर आने के लिए कह दिया जाता है। एसआईआर के काम में जिले भर में 699 बीएलओ लगे हुए हैं। कोतमा में 202, अनूपपुर में 224 एवं पुष्पराजगढ़ में 273 है।

जानकारी देना जरूरी

मतदाता पुनरीक्षण गणना पत्रक में मतदाताओं के नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, माता-पिता का नाम और उनका ईपिक नंबर दर्ज किया जा रहा है। साथ ही पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में निर्वाचन का नाम, इपिक नंबर, रिश्तेदार का नाम, रिश्ता, जिला तथा राज्य का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम भी दर्ज किया जा रहा है। जिस रिश्तेदार का नाम बताया जा रहा है उसका ईपिक नंबर, रिश्ता तथा जिले का नाम और राज्य तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र इसमें दर्ज किया जा रहा है। वर्तमान में जिले में कुल 537225 मतदाता हैं। कोतमा विधानसभा में 152217 मतदाता, अनूपपुर 180875 जबकि पुष्पराजगढ़ में कुल 204133 मतदाता दर्ज हैं।

सर्वर की हो रही परेशानी

कोतमा वार्ड 06 के बीएलओ दशरथ पनिका ने बताया कि 2003 के मतदान से संबंधित जानकारी मतदाताओं के पास नहीं है और ना ही वह इससे संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर पा रहे हैं। मतदाता से संबंधित पोर्टल पर यह जानकारी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन यह वेबसाइट इतना व्यस्त रहती है कि हर वक्त काम नहीं हो पाता है। एक मतदाता की जानकारी ढूंढने में 15 से 20 मिनट का समय लग जा रहा है। बीएलओ केंद्र अंतर्गत 750 मतदाताओं की जानकारी दर्ज की जानी है। वार्ड 06 निवासी दीप्ति गुप्ता ने बताया 2003 से संबंधित जानकारी बीएलओ भी रिकॉर्ड ढूंढने का प्रयास करते हैं। अधिकतर मतदाताओं के पास इतनी

पुरानी जानकारी नहीं है। शासन को यह जानकारी फॉर्म में दर्ज करके फार्म वितरण करना चाहिए था। नागरिकों ने बताया कि सारी जानकारी दर्ज कर दी, लेकिन 2003 के मतदान से संबंधित जानकारी नहीं मिल पा रही है। साथ ही महिलाओं की जानकारी मगाने में भी परेशान होना पड़ रहा है इतना ही नही दूसरे राज्य के व्यक्तियों को भी जहां पहले रह रहे थे वहा से जानकारी जुटाने मे परेशानी हो रही है बीएलओ के पास भी यह जानकारी नहीं है। मतदाता कैसे जानकारी दर्ज करें। घर के सभी सदस्यों को इसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।

अभी तक नही बांटे गए फार्म

कोतमा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक दो निवासी विनोद सराफ, रजनी सोनी, अरुण कुमार, राकेश तिवारी लक्ष्मीकांत द्विवेदी सहित अन्य ने बताया कि 4 नवम्बर से यस आई आर का पत्रक वितरण कार्य शुरू हुआ है लेकिन हमारे बी यल ओ के द्वारा अभी तक फार्म घर मे नही पहुंचाया गया है। जबकि 14 दिन का समय बीतने को है और हमें फार्म उपलब्ध नही करवाया गया है। जबकि यह निर्देश दिए गए हैं कि 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक बीएलओ घर घर पहुंच कर फार्म उपलब्ध करवाते हुए फार्म भरेगे। एसआईआर के कार्य की मानीटरिग के लिए कोतमा नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों मे यस डी यम टी आर नाग, तहसीलदार दशरथ सिंह, नगर पालिका सीएमओ प्रदीप झारिया, पटवारी अभिमन्यु पाल के साथ मंगलवार को कोतमा नगर पालिका क्षेत्र मे भ्रमण करते हुए घर घर पहुंच मतदाताओं को फार्म भरने एवं हो रही परेशानी से अवगत होते हुए निदान करने मे जुटे हैं। साथ ही किसी को जानकारी ना उपलब्ध होने पर तनाव में आए बीएलोओ, राजस्व एवं नपा कर्मचारी आपके पास पहुंचकर सहायता के लिए टीम फील्ड में मौजूद हैं।

इधर लापरवाही पर बीएलओ निलंबित

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षल पंचोली ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 87-अनूपपुर के मतदान केन्द्र क्रमांक 31 जमुड़ी की बीएलओ श्रीमती राजकुमारी सिंह को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में लापरवाही बरतने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 (वर्गीकरण एवं अपील), नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। संकुल केन्द्र शा. उ.मा.वि. सकरा के प्राथमिक शाला छीरापटपर की संविदा शिक्षक वर्ग-3 तथा बीएलओ श्रीमती राजकुमारी सिंह को एसआईआर कार्य अंतर्गत गणना पत्रक का वितरण एवं डिजीटाईजेशन का दायित्व सौपा गया था, किन्तु उनके द्वारा उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फेक दिया गया एवं कोई कार्य नहीं किया गया है। इस तरह सौंपे गए दायित्वों के प्रति अनुशासनहीनता करने और निर्वाचन कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अनूपपुर में नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

प्रगति की उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय श्रीवास्तव ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य के प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशानिर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार पाण्डेय, विधानसभा क्षेत्रों के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, बीएलओ सहित एसआईआर कार्य में संलग्न अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बीएलओ, बीएलओ सुपरवाईजर तथा एसआईआर कार्य में संलग्न कर्मचारी प्रत्येक बीएलओ स्तर पर प्रतिदिन 100 गणना पत्रक का संग्रहण कर डिजिटलाईजेशन की कार्यवाही करें। एसआईआर का कार्य गंभीरता और प्राथमिकता के साथ करें। एसआईआर कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। उन्होंने कहा कि जिले के शत प्रतिशत मतदाताओं तक समय पर गणना पत्रक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कार्य की गति बढ़ाने तथा निर्वाचन आयोग द्वारा चाही गई जानकारी तत्परता से बीएलओ एप में अपडेट करने के संबंध में निर्देश दिए।

शिक्षा के मंदिर में दो शिक्षकों के बीच झूमा-झटकी

हरिभूमि न्यूज कोतमा।

मंगलवार को शासकीय मार्तंड महाविद्यालय में खेल शिक्षक मीना मिश्रा की शर्मनाक करतूत ने शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया। महिला के द्वारा अतिथि शिक्षक रंजना सिंह के साथ गलियां देते हुये जमकर अभद्रता करते हुए मारपीट की गई।

घटना से पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया। छात्राएं एवं अन्य महिला शिक्षक शर्मसार होकर कॉलेज छोड़कर चली गई। महिला टीचर रंजना सिंह द्वारा थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार दोपहर ढाई बजे के लगभग मीना मिश्रा द्वारा अश्लील गाली गलौज की जाती रही जिसके बाद वह दूर चली गई। जिसके बाद फिर से दोबारा अश्लील एवं अभद्रता करने के साथ बाल खींचकर मारपीट की गई। कॉलेज परिसर में हुई घटना के बाद अन्य टीचर एवं छात्रों के द्वारा थाना पहुंच शिकायत दर्ज कराई गई। बताया जाता है कि जब से मीना मिश्रा की पोस्टिंग हुई है तब से कॉलेज में विवाद की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। शिक्षा के मंदिर का वातावरण भी बिगड़ता जा रहा है।

इनका कहना है

कुछ दिनों पूर्व ही प्रिंसिपल के साथ भी अभद्रता एवं मीना मिश्रा के द्वारा भी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। दोनों पक्षों के द्वारा शिकायत की गई है। मामले की जांच कराई जा रही है।
रत्नाम्बर शुक्ल थाना प्रभारी कोतमा

थोड़ा प्रशिक्षण लेकर सीखी जा सकती है जान बचाने की टेक्निक

ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों में अब ट्रैफिक मित्र बनेंगे 'आपदा मित्र'

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रशिक्षित किए जा रहे ट्रैफिक मित्र

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

सड़क दुर्घटना के दौरान घायल व्यक्ति को समय पर प्राथमिक उपचार मिले तो उसके जीवन को बचाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि लोगों को जानकारी हो कि घायल को प्राथमिक इलाज किस तरह किया जाए। जिले के विभिन्न ब्लैक स्पॉट्स के आसपास रहने वाले ट्रैफिक मित्रों को डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम द्वारा सीपीआर और बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान के निर्देश पर ऑन द स्पॉट प्रदर्शित किया गया। जिसके तहत पूरे जिले में एक सक्षम, प्रशिक्षित और संवेदनशील ट्रैफिक मित्र टीम तैयार की जा रही है, जो दुर्घटना के समय तत्काल मदद पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। अनूपपुर पुलिस का उद्देश्य है कि हर ब्लैक स्पॉट पर ऐसे आपदा मित्र मौजूद हों, जो आपात स्थिति में स्वर्णिम समय को बचाते हुए लोगों की जान बचा सकें।

जान बचाने का आसान तरीका

बुधवार को प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टरों ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर घायल की स्थिति

पहचानने, प्राथमिक उपचार देने तथा सीपीआर तकनीक का लाइव डेमो प्रस्तुत किया। प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाने से पहले किन सावधानियों का पालन आवश्यक है। इस दौरान बताया गया कि सड़क हादसों में कई बार घायल व्यक्ति की जान इसलिए नहीं बचती, क्योंकि घटनास्थल पर मौजूद लोग प्राथमिक उपचार देने के तरीके नहीं जानते। उन्होंने कहा कि सीपीआर एक ऐसी तकनीक है जिसे कोई भी व्यक्ति थोड़े प्रशिक्षण के बाद सीख सकता है। यह तकनीक हृदय गति रुक जाने की स्थिति में किसी की जान बचाने में प्रभावी होती है। सीपीआर देने में टाइमिंग का महत्व है। घायल या मरीज को कितनी बार हार्ट पॉपिंग की जाए और उसका प्रेशर कितना हो यह जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए डॉक्टर की मौजूदगी में प्रशिक्षण लेकर यह टेक्निक सीखना बेहद आसान है।

स्कूल-कालेजों मे भी देंगे प्रशिक्षण

डॉक्टर ने लोगों को बताया कि घटना के दौरान घबराएं नहीं, बल्कि स्थिति को संभालते हुए तुरंत सीपीआर देना शुरू कर एंबुलेंस को कॉल करें, ताकि मेडिकल टीम समय पर पहुंच सके। पुलिस ने बताया कि शहर के स्कूलों, कॉलेज, सरकारी विभाग, ड्राइविंग स्कूलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रशिक्षित हो सकें। प्रशिक्षण के दौरान सीपीआर की पूरी प्रक्रिया का प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन दिया गया। प्रशिक्षकों ने बताया कि सीपीआर के समय छाती पर दबाव और मुंह से सांस देने की तकनीक बेहद सटीक और संतुलित होनी चाहिये। पुलिस ने कहा कि दुर्घटना का मुख्य कारण वाहन ओवर स्पीड मे होना और लापरवाही बरतना होता है। कुछ सेकंड की लापरवाही लोगों की जिंदगी छीन लेती है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों को अगर सीपीआर देने की जानकारी हो तो कई जिंदगी बचाई जा सकती हैं। शहर में कई स्थानों को ब्लाइंड स्पॉट घोषित किया गया है जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे स्थानों पर जागरूकता और त्वरित मदद बेहद आवश्यक है।

कैंप लगाकर बैंकर्स स्वरोजगार योजनाओं के ऋण वितरण कार्य में लाएं तेजी

जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक हुई आयोजित

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

कलेक्टर हर्षल पंचोली की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में सोमवार को जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर ने सभी बैंकर्स को निर्देश देते हुए कहा कि गंभीरता के आधार पर कैंप लगाकर विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के हितग्राहियों के प्रकरणों का समय पर निष्पादन कर ऋण उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं के प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान करना, केवल लक्ष्य पूर्ति का मामला नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य जरूरतमंद हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। कलेक्टर ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि वे विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के विभागों के लक्ष्य के अनुरूप बैंकों में पहुंचने वाले स्वरोजगार के

प्रकरणों के निराकरण में सकारात्मकता और संवेदनशीलता दिखायें। ताकि रोजगार-स्वरोजगार की दिशा में लोग आगे बढ़ें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। इसके लिये जरूरी है कि बैंकर्स समय पर आवेदनों पर ऋण वितरण सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग, उद्यानिकी विभाग, एनआरएलएम, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत सभी बैंकों को लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि अर्जित करने, पशुपालन, मत्स्य पालन, शहरी विकास अभिकरण, एनआरएलएम एवं जनजातीय कार्य विभाग, अंत्यावसायी, वित्त विकास निगम और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को योजनाओं के लिये तय लक्ष्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिये। बैठक में कलेक्टर ने पिछली डीएलसीसी में दिये गये निर्देशों का पालन, वार्षिक साख योजना, सीएम हेल्पलाइन, ऋण वसूली, आरसीसी, स्वसहायता समूहों को बैंक लिंकेज, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की तथा निर्देशित किया कि लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु कैंप लगाया जाए तथा सीआर रेशियों को भी बढ़ाया जाए।

ठंडे बस्ते में सचिव प्रभार पर शासन का आदेश

सहायक सचिव संगठन के जिलाध्यक्ष की शिकायत पर भी प्रशासन मौन

हरिभूमि न्यूज अनूपपुर।

ग्राम पंचायतों में सचिव रिक्त होने पर सहायक सचिव को प्रभार देने के शासनादेश का अनूपपुर जिले में पालन नहीं किया जा रहा है 4 सितंबर तथा 11 नवंबर के राजपत्रित नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी स्थिति में एक सचिव को दो या अधिक पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जाए इसके बावजूद जिले की कई पंचायतों में यही व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिससे पंचायतों के विकास कार्य और हितग्राही सेवाएँ प्रभावित हो रही हैं। सहायक सचिव संगठन ने इस अव्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है संगठन के जिला अध्यक्ष चंद्रभान यादव ने व्यक्तिगत रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अनूपपुर को सचिवीय प्रभार से संबंधित लिखित आवेदन भी प्रस्तुत किया था, लेकिन आज दिनांक तक उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला अध्यक्ष चंद्रभान यादव का कहना है कि शासन के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद जिला स्तर पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है कई सचिव दो-दो पंचायतों का काम संभाल रहे हैं, जबकि सहायक सचिव प्रभार मिलने की प्रतीक्षा में हैं इससे समय पर भुगतान, प्रमाणपत्र प्रक्रिया, जनसुनवाई, निर्माण कार्य प्रस्ताव तथा ऑनलाइन प्रविष्टियाँ गंभीर रूप से बाधित हैं। उन्होंने कहा कि मंडला, डिंडोरी, शहडोल और उमरिया जैसे जिलों में शासन आदेश का पालन किया जा चुका है, लेकिन अनूपपुर में आदेश "धारा का धरा" रह गया है। समाचार प्रकाशन के बाद भी प्रशासन की चुप्पी यह दर्शाती है कि न कोई सुनवाई हो रही है, न ही किसी के कान में जूँ तक रेंग रही है। सहायक सचिव संगठन ने जिला पंचायत प्रशासन से पुनः मांग की है कि शासन आदेश का तत्काल पालन करवाया जाए, सचिव-विहीन पंचायतों में सहायक सचिव को ही सचिवीय प्रभार दिया जाए तथा एक सचिव को केवल एक ही पंचायत का दायित्व सौंपा जाए। जिला पंचायत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।